



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 140]
No. 140]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 20, 1986/ज्येष्ठ 30, 1908
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 20, 1986/JYAISTHA 30, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as
a separate compilation

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 जून, 1986

संकल्प

फा० सं० 11012/4/85-एस०आर०.—भारत सरकार ने
दिनांक 2 अप्रैल, 1986 के अपने संकल्प सं० 11012/4/85-
एस०आर० के तहत, दिनांक 24 जुलाई, 1985 के
समझौता-विवरण (पंजाब समझौता) के पैरा 7.2 के
अनुसार, एक आयोग नियुक्त किया जिसके अध्यक्ष भारत के
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री ई० एस०
वेंकटरमैया थे।

2. आयोग ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट 10 जून,
1986 को प्रस्तुत की। आयोग ने, अपनी सिफारिशें देते
हुए, अन्य बातों के साथ-साथ, यह निर्धारित किया कि
चंडीगढ़ के बदले हरियाणा का पंजाब से लगभग 70,000
एकड़ भूमि-क्षेत्र अन्तर्गत किया जाना चाहिये। तथापि,
आयोग उन क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करने की स्थिति में नहीं
था, जो उसके अधिनिर्णय में यथा-निर्धारित 70,000 एकड़
के अन्तर्गत आएं, जिन्हें कि अन्तर्गत किया जाना चाहिये।

3. न्यायमूर्ति श्री वेंकटरमैया के अधिनिर्णय को ध्यान
में रखते हुए और 21 जून, 1986 को पंजाब को चंडीगढ़
के साथ-साथ उसके बदले क्षेत्रों को हरियाणा को अन्तर्गत
करने संबंधी भारत सरकार के संकल्प को ध्यान में रखते
हुए, भारत सरकार ने चंडीगढ़ के बदले हरियाणा को पंजाब
में अन्तर्गत किये जाने वाले क्षेत्रों को, जो लगभग 70,000
एकड़ हों, विनिर्दिष्ट करने का प्रश्न भारत के उच्चतम
न्यायालय के सेवा-निवृत्त न्यायाधीश और भारत के विधि
आयोग के अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति श्री डा० ए० देसाई
को निर्दिष्ट करने का निर्णय किया है जिनके नाम को
भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा सिफारिश का
गई है। न्यायमूर्ति श्री के० के० मधु का रिपोर्ट और न्याय-
मूर्ति श्री ई० एस० वेंकटरमैया का रिपोर्ट सहित सभी संगत
सामग्री माननीय न्यायमूर्ति श्री डा० ए० देसाई को सौंपी जा
रही है।

4. माननीय न्यायमूर्ति श्री डा० ए० देसाई अपना कार्य-
विधि स्वयं तैयार करेंगे जिसके लिये वह इस प्रश्न से संगत
सभी रिकार्डों को किस भी प्राधिकारी से मांग सकते हैं

और उनका परिणाम करने के बाद, क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करते हुए अपने निष्कर्ष अभिलिखित करेंगे।

5. पंजाब से हरियाणा को अन्तर्गत किये जाने वाले क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करने संबंधी सिफारिशें भारत सरकार को अधिक से अधिक 21 जून, 1986 के पूर्वान्त तक प्रस्तुत की जायेंगी।

आर० डी० प्रधान, सचिव

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रतिलिपि सभी राज्य सरकारों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, आदि को भेजी जाए और यह भी कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतिलिपि आयोग को भेजी जाए।

आर० डी० प्रधान, सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 20th June, 1986

RESOLUTION

F. No. 11012/4/85-SR.—Government of India, *vide* its Resolution No. 11012/4/85-SR dated the 2nd April, 1986, appointed a Commission in terms of para 7.2 of the Memorandum of Settlement dated the 24th July, 1985 (Punjab Accord) consisting of Hon'ble Shri Justice E.S. Venkataramiah, Judge of the Supreme Court of India.

2. The Commission submitted its report to the Government of India on 10th June, 1986. The Commission in giving its recommendations has *inter-alia* determined that about an area of 70,000 acres of land should be transferred from Punjab to Haryana in lieu of Chandigarh. The Commission was, however, not in a position to specify the areas which would be

constituting 70,000 acres as determined in its award that should be transferred.

3. Having regard to the award of Shri Justice Venkataramiah and also having regard to the Government of India's resolve to transfer Chandigarh to Punjab on 21st June, 1986 simultaneously with the territories in lieu thereof to Haryana, the Government of India have decided to refer the question of specifying the territories consisting of about 70,000 acres to be transferred from Punjab to Haryana in lieu of Chandigarh to Hon'ble Shri Justice D. A. Desai, Retired Judge, Supreme Court of India and Chairman, Law Commission of India, whose name has been recommended by the Hon'ble Chief Justice of India. All the relevant materials including the report of Shri Justice K.K. Mathew and the report of Shri Justice E. S. Venkataramiah are being placed at the disposal of Hon'ble Shri Justice D.A. Desai.

4. Hon'ble Shri Justice D.A. Desai will devise his own procedure in that he may call for all records relevant to the issue from any authority and after perusing the same, record his findings specifying the areas.

5. The recommendations specifying the areas to be transferred from Punjab to Haryana will be submitted to the Government of India not later than the forenoon of 21st June, 1986.

R. D. PRADHAN, Secy.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments, all Ministries of the Government of India, etc., and also that the Resolution be published in the Gazette of India.

Ordered also that a copy of the Resolution be communicated to the Commission.

R. D. PRADHAN, Secy.